अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 02 | श्री विजय पुरम, | शुक्रवार, 02 जनवरी 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का द्वीपों का दौरा 2 से 4 जनवरी तक

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्य 2 से 4 जनवरी तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दौरे पर रहेंगे। आगमन के शीघ्र पश्चात समिति के सदस्य राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का भ्रमण करेंगे तथा लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की प्रोटोकॉल इकाई से प्राप्त आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 3 जनवरी को श्री विजय पुरम में सीएफएसएल–एनएफएसयू के संबंध में गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे को ध्यान में रखते हुए यातायात परामर्श

सहायता के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नम्बर 03192–243812, व्हाट्सएप 9531892228 संपर्क करें

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

यह सूचित किया जाता है कि आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे को ध्यान में रखते हुए तथा वाहनों की सुचारु एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ उपाय किए जाएंगे। साथ ही, आम जनता की आवागमन सुविधा के लिए कुछ स्थानों पर वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी सूचना नीचे अनुसार दी जाएगी।

03.01.2026 (शनिवार)		
मुख्य मार्ग	वैकल्पिक मार्ग	समय
नेताजी स्टेडियम, अग्निशमन मुख्यालय, सचिवालय, डॉलीगंज, भातूबस्ती, गाराचरमा, सीपीघाट, धानीखाड़ी	आरजीटी रोड–हवाघर जंक्शन नया गांव–चक्करगांव–कार्बिन चौक जंक्शन,–भातूबस्ती (इसके विपरीत)	दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक

हवाई अड्डे की यात्रा, परीक्षा में सम्मिलित होने, चिकित्सीय आवश्यकताओं अथवा किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करें या व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। ऐसे आवागमन के लिए अण्डमान तथा निकोबार ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी।

किसी भी स्थान पर सड़क अवरोध या मार्ग बंद नहीं किया जाएगा। यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने, जाम की स्थिति से बचने तथा शहर भर में वाहनों की सुचारु आवाजाही बनाए रखने के लिए वैकल्पिक यातायात मार्ग योजना लागू की गई है।

यातायात के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी सुगम एवं सुरक्षित आवागमन में सहायता प्रदान करेंगे।

वीआईपी दौरे के मद्देनज़र ड्रोन के उपयोग संबंधी निषेधात्मक आदेश जारी

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

दक्षिण अण्डमान ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्र संख्या एसएसपी (डी) एसए/वीआईपी/2025/5383 दिनांक 22 दिसंबर, 2025 के माध्यम से 2 जनवरी, 2026 से 4 जनवरी, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की वीआईपी यात्रा के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किया है। वीआईपी दक्षिण अण्डमान ज़िले में विभिन्न स्थानों का दौरा करने वाले है, मौजूदा सुरक्षा चिंताओं और हालिया आतंकवादी खतरों के कारण कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िलाधीश, दक्षिण अण्डमान ज़िला द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत सभी दूर से संचालित विमान प्रणालियों (आरपीए)/ड्रोन के साथ–साथ पैरा–ग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग, या इसी तरह की हवाई गतिविधियों सहित किसी भी हवाई गतिविधियों का उड़ान, संचालन या उपयोग वीर सावरकर इंटरनेशनल (वीएसआई) हवाई अड्डा, आईटीएफ ग्राउंड, डीब्राइट, लोक निवास, वंडूर, चिडियाटापू और नेताजी स्टेडियम क्षेत्र आदि स्थानों पर और उसके आसपास निषिद्ध है।

दक्षिण अण्डमान ज़िले के ज़िलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेध 02.01.2026 से 04.01.2026 तक लागू रहेगा, और ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से लागू किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के साथ–साथ विमान अधिनियम, 1934, ड्रोन नियमों या लागू किसी अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों सहित कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत सज़ा के लिए उत्तरदायी होगा।

सार्वजनिक कार्यक्रमों में वस्तुएँ ले जाने पर प्रतिबंध

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनवरी, 2026 के प्रथम सप्ताह के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में वीवीआईपी के आगमन एवं उनके द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के मद्देनज़र, पुलिस व्यवस्था की तैयारियों के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से आमंत्रित अतिथियों एवं आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे वीवीआईपी द्वारा भाग लिए जाने वाले कार्यक्रम स्थलों पर माला, गुलदस्ता, पावर बैंक, बैटरी चालित खिलौने, सिक्के, पेजर, कैमरा, दूरबीन, सिगरेट, लाइटर, माचिस, हैंडबैग, छाता, पानी की बोतल, पैकेट, ब्रीफकेस, ट्रांसमीटर, टिफिन बॉक्स, काँच की वस्तुएँ, स्क्रू ड्राइवर आदि जैसे नुकीले/तेजधार वस्तुएँ इत्यादि वस्तुएँ साथ न लाएँ।

बृंदाबन पंचायत में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के विरूद्ध जागृति लाई गई

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 30 दिसंबर, 2025 को दक्षिण अण्डमान की बृंदाबन ग्राम पंचायत में किया गया। यह कार्यक्रम ज़िला प्रशासन, दक्षिण अण्डमान के अंतर्गत संचालित एकीकृत नशा पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) द्वारा, सामाजिक कल्याण निदेशालय के एनएपीडीडीआर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के एनटीसीपी तथा अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की एंटी–नारकोटिक्स (सीआईडी) शाखा के सहयोग से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जनता एवं ग्राम पंचायत बृंदाबन के पीआरआई सदस्यों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत बृंदाबन की प्रधान श्रीमती एम. ए. नसीम बानू तथा ज़िला परिषद सदस्य श्री यू. के. अब्दुल अज़ीज़ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

डॉ. एम. के. महतो, चिकित्सा अधिकारी (डीडीआर/आईआरसीए),

दक्षिण अण्डमान ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा नशे से बचने के उपाय बताए। श्री रथिंद्र मलिक, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं उससे बचाव के तरीकों की जानकारी दी तथा कोटपा अधिनियम के प्रावधानों पर भी चर्चा की। शेष पृष्ठ 4 पर

डिजिटल हुई लगभग 2 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी

डिजिटल सब्सिडी विकसित भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदमः केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 01 जनवरी। (प.सू.का.)

भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने साल 2026 के पहले दिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं। विभाग ने लगभग दो लाख करोड़ की सालाना सब्सिडी को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला लिया है।

इस अहम मुहिम की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली के कर्तव्य भवन से की।

श्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उर्वरक विभाग की इस पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है. उन्होंने कहा कि पूरे ईकोसिस्टम के डिजिटल हो जाने से विभाग से जुड़ी कंपनियों और उनके माध्यम से सभी किसानों को सुविधा होने जा रही है।

इस दौरान उर्वरक सचिव श्री रजत कुमार मिश्र ने कहा कि यह फैसला बिलों से पेपर हटाने तक सीमित नहीं है। उर्वरक उद्योग को इस फैसले से नई गति मिलेगी। नए बिलिंग सिस्टम में आधुनिक तकनीक का इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि जिससे रॉ मैटिरियल से फाइनल प्रॉडक्ट बनने की पूरी प्रक्रिया एक जगह आ जाएगी और उसे किसी भी स्तर से मॉनिटर किया जा सकेगा।

दरअसल भारत सरकार के उर्वरक विभाग ने अपने साथ काम करने वाले सभी पीएसयू, सहकारी संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों से वित्तीय लेनदेन को आईएफएमएस के जरिए वित्त मंत्रालय के पहले से चले आ रहे पीएफएमएस के साथ जोड़ दिया है।

मुख्य लेखा नियंत्रक श्री संतोष कुमार ने बताया कि यह उपलब्धि आईएफएमएस और पीएफएमएस के बीच विशिष्ट तकनीकी साझेदारी का महत्वपूर्ण परिणाम है. उन्होंने कहा कि

इस बदलाव के बाद उर्वरक विभाग के सभी वित्तीय लेन–देन डिजिटल हो जाएंगे. इस प्रणाली के जरिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास सुविधा रहेगी कि वो किसी भी समय सीधी निगरानी कर सकेंगे।

संयुक्त सचिव श्री मनोज सेठी ने बताया कि नई डिजिटल प्रणाली से सब्सिडी बिलों के भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी और साप्ताहिक सब्सिडी समय पर जारी की जा सकेगी. 'ई–बिल' पोर्टल की सुविधा से खाद कंपनियां अब ऑनलाइन क्लेम जमा कर रियल–टाइम में अपने पेमेंट की स्थिति देख सकेंगी. इस पहल से सरकारी दतरों के चक्कर लगाने और कागजी कार्रवाई की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी।

कार्यक्रम में अपर सचिव श्रीमती अनीता सी. मेश्राम, अपर सचिव श्रीमती अपर्णा शर्मा, संयुक्त सचिव श्री के.के. पाठक तथा संयुक्त सचिव श्री अनुराग रोहतगी, निदेशक मिस लाबुनी दास दत्ता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री असीम गुप्ता, संयुक्त निदेशक श्री अशुतोष तिवारी और डेवलपर श्री हरे कृष्ण तिवारी शामिल रहे।

जिप अध्यक्ष ने दी नववर्ष की शुभकामनाएँ

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

ज़िला परिषद, दक्षिण अण्डमान के अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी ने नववर्ष 2026 के शुभ अवसर पर समस्त द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाला वर्ष अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोगों के लिए शांति, समृद्धि एवं सर्वांगीण कल्याण लेकर आएगा।

स्मार्ट पीडीएस 2.0 में राशन कार्ड विवरण अद्यतन करना अनिवार्य

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने सभी राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया है कि स्मार्ट पीडीएस 2.0 प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में राशन कार्डों में जानकारी अधूरी या त्रुटिपूर्ण है।

पूरा पता पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर, गांव/वार्ड नंबर, तहसील, ज़िला तथा अन्य अनिवार्य विवरण अधूरे होने के कारण राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं जैसे अद्यतन, संशोधन एवं अन्य लाभार्थी सेवाओं के सत्यापन और प्रक्रिया में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे राशन कार्ड निरस्त होने की संभावना भी हो सकती है।

स्मार्ट पीडीएस 2.0 प्रणाली के सुचारू संचालन एवं सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल **an.smartpds.nic.in** पर जाकर स्व–सेवा ऑनलाइन माध्यम से अपने राशन कार्ड विवरण अनिवार्य रूप से अद्यतन या संशोधित करें।

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी अनिवार्य कॉलम सही–सही भरें। उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) के संचालक अपने संबंधित राशन कार्ड लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन में सहायता करेंगे।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थी नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, श्री विजय पुरम (कक्ष संख्या–24) अथवा अपनी संबंधित आपूर्ति इकाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल एवं पारदर्शी संचालन हेतु सभी लाभार्थियों से सहयोग की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर 03192–230337 पर संपर्क किया जा सकता है।

मोटर वाहन पंजीकरण के लिए नई श्रृंखला 'एएन01–डब्ल्यू' 5 जनवरी से उपलब्ध

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

आम जनता को सूचित किया गया है कि मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए 'एएन01–डब्ल्यू' श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न 5 जनवरी से आरक्षण हेतु उपलब्ध होंगे, क्योंकि वर्तमान में चल रही 'एएन01–टी' श्रृंखला समाप्ति के निकट है।

जो वाहन स्वामी अपनी पसंद का पंजीकरण चिह्न आरक्षित कराना चाहते हैं, वे निम्नलिखित श्रृंखलाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

1. यू–श्रृंखला (यह सामान्य रूप से चलने वाली श्रृंखला होगी)
2. वी–श्रृंखला
3. डब्ल्यू–श्रृंखला

परिवहन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि जो वाहन स्वामी पूर्व की श्रृंखला में बचे हुए पंजीकरण चिह्नों को बुक करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञान केंद्र में 'स्काई शो', शनि और चंद्रमा का होगा अवलोकन आज

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

विज्ञान केंद्र, कार्बिन रोड, श्री विजय पुरम द्वारा 2 जनवरी को शाम 5.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक 'स्काई शो' का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में चंद्रमा तथा शनि ग्रह एवं उसके उपग्रहों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आगंतुकों को श्री विजय पुरम के आकाश का स्काई मैप भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की पहचान कर सकें। इसके अलावा, शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से शनि ग्रह के विशाल छल्लों (लॉर्ड ऑफ द रिंग्स) तथा चंद्रमा और उसके गड्ढों को देखने का रोमांचक अनुभव भी मिलेगा। स्काई शो की प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 10 रुपये है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके साथ ही, शाम 5.30 बजे और शाम 6.10 बजे विशेष 3डी शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपये है।

खेलो इंडिया जनजातीय खेल–2026 के लिए चयन परीक्षण

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2026 के दौरान छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के प्रथम संस्करण का आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य खेल कौशल को प्रदर्शित करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना तथा विशेष रूप से जनजातीय युवाओं (ओपन आयु वर्ग) के लिए प्रतिभाशाली एवं मेधावी युवाओं की पहचान कर उनके विकास मार्गों को सुदृढ़ बनाते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

इस संदर्भ में, अण्डमान तथा निकोबार खेल दल के गठन हेतु, खेल एवं युवा कार्य निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा पात्र जनजातीय युवाओं के लिए 6 एवं 7 जनवरी, 2026 को विभिन्न खेल विधाओं में राज्य स्तरीय चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति में इच्छुक जनजातीय युवाओं से अनुरोध किया गया है कि वे चयन परीक्षणों में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा जारी निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित हों–

1. मूल अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र तथा उसकी दो स्वप्रमाणित प्रतियाँ
2. मूल राज्य डोमिसाइल प्रमाणपत्र तथा उसकी दो स्वप्रमाणित प्रतियाँ (आइलैंडर कार्ड/स्थानीय प्रमाणपत्र आदि)

राज्य स्तरीय चयन परीक्षणों का कार्यक्रम एवं स्थान

क्र.सं.	खेल विधा	तिथि व समय	स्थान
1.	फुटबॉल–पुरुष	6 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	बीजेआर स्टेडियम, कार निकोबार
2.	फुटबॉल–महिला	7 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	
3.	हॉकी–पुरुष	6 जनवरी, 2026, सुबह 10 बजे	
4.	हॉकी–महिला	7 जनवरी, 2026, सुबह 10 बजे	
5.	एथलेटिक्स–पुरुष	6 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स, लपाती, कार निकोबार
6.	एथलेटिक्स–महिला	7 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	
7.	वेटलिफ्टिंग–पुरुष	6 जनवरी, 2026, सुबह 10 बजे	
8.	वेटलिफ्टिंग–महिला	7 जनवरी, 2026, सुबह 10 बजे	
9.	स्विमिंग–पुरुष	6 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	स्विमिंग पूल तथा तीरंदाजी रेंज, नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स, श्री विजय पुरम
10	स्विमिंग–महिला	7 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	
11	आर्चरी–पुरुष (रिकर्व और कंपाउंड)	6 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	
12	आर्चरी–महिला (रिकर्व और कंपाउंड)	7 जनवरी, 2026, सुबह 8 बजे	

किसी भी अन्य जानकारी/पूछताछ के लिए कृपया श्री जी. नागेश राव, पीईटी (मोबाइल 7063974074) तथा श्री ए. जी. प्रवीन राव, पीईटी (मोबाइल 9474230278) से संपर्क करें।

14वीं राष्ट्रीय विद्यालय शतरंज चैंम्पियनशिप में द्वीपों के शतरंज खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय

श्री विजय पुरम, 31 दिसंबर

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के युवा शतरंज प्रतिभाओं जे. एस. विराट एवं एस. भविष्या ने गुवाहाटी, असम के सरुसजाई इंडोर स्टेडियम में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय विद्यालय शतरंज चैंम्पियनशिप 2025 में सराहनीय प्रदर्शन किया, जिसका समापन कल हुआ। 27 से 31 दिसंबर, 2025 तक आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने अंडर–7 से अंडर–17 तक की 12 श्रेणियों में भाग लिया।

अंडर–13 वर्ग में जे. एस. विराट ने पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए 9 राउंड में 6.5 अंक अर्जित किए, आठवां स्थान प्राप्त किया, शीर्ष दस खिलाड़ियों में स्थान बनाया तथा राष्ट्रीय स्तर पर पदक एवं नकद पुरस्कार जीता।

अंडर–17 बालिका वर्ग में एस. भविष्या ने 9 राउंड में 5.5 अंक प्राप्त कर नौवां स्थान हासिल किया, शीर्ष दस खिलाड़ियों में शामिल हुईं तथा राष्ट्रीय स्तर पर पदक एवं नकद पुरस्कार अर्जित किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अन्य छह खिलाड़ियों–एसीएम दिशा मीनाक्षी जी. (अंडर–11 बालिका), एसीएम सॉ जिन्सन सैमुअल (अंडर–9), एसीएम अग्रता सिंह (अंडर–13 बालिका), एसीएम नुहान सिद्दीक़ी वी. के. (अंडर–7), एसीएम अग्रिमा सिंह एवं एसीएम प्रिया सिंह (अंडर–13 बालिका)–ने भी अपनी–अपनी आयु श्रेणियों में सराहनीय प्रदर्शन किया।

ओपन स्टेट क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं चयन ट्रायल 4 जनवरी को

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एथलेटिक्स संघ ने अण्डमान तथा निकोबार राज्य ओलंपिक संघ के सहयोग से 4 जनवरी, 2026 को श्री विजय पुरम में ओपन स्टेट क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026 एवं चयन ट्रायल आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। यह चैंपियनशिप पुरुष, महिला, अंडर–20 वर्ष (बालक एवं बालिकाएँ), अंडर–18 वर्ष (बालक एवं बालिकाएँ) तथा अंडर–16 वर्ष (बालक एवं बालिकाएँ) श्रेणियों के लिए आयोजित की जाएगी। क्रॉस कंट्री दौड़ की प्रतियोगिताएँ एवं दूरियाँ निम्नानुसार होंगी:

पुरूषों		महिला		आयु वर्ग
दौड़	दूरी	दौड़	दूरी	
पुरुषों	10 किमी	महिला	10 किमी	खुला
अंडर–20 लड़के	8 किमी	अंडर–20 लड़कियां	6 किमी	25.01.2006 और 24.01.2008 के बीच जन्मे
अंडर–18 लड़के	6 किमी	अंडर–18 लड़कियाँ	4 किमी	25.01.2008 और 24.01.2010 के बीच जन्मे
अंडर–16 लड़के	2 किमी	अंडर–16 लड़कियाँ	2 किमी	25.01.2010 और 24.01.2012 के बीच जन्मे

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार चयनित खिलाड़ियों को 24 जनवरी, 2026 को प्रभात तारा मैदान, जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एचईसी, रांची (झारखंड) में आयोजित होने वाली आगामी 60वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2026 में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाएगा। संघ ने खिलाड़ियों से ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से अपनी प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। चैंपियनशिप के लिए पृथक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा तथा खिलाड़ियों को 3 जनवरी, 2026 से पूर्व ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

रेंजर पद के लिए लिखित परीक्षा केन्द्र में बदलाव

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत वन रेंजर पद हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित वीवीआईपी यात्रा के मद्देनज़र 3 जनवरी, 2026 एवं 4 जनवरी, 2026 को 'डीब्राइट' में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र/स्थल नीचे दर्शाए अनुसार परिवर्तित कर दिया गया है।

क्र.सं.	विषय	तारीख	दिन	समय	कार्यक्रम का स्थान
1	कंप्यूटर अनुप्रयोग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान	03/01/2026	शनिवार	सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक	कार्मेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री विजय पुरम
2	वानिकी, भौतिकी	03/01/2026	शनिवार	दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक	कार्मेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री विजय पुरम
3	सामान्य ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी	04/01/2026	रविवार	सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक	कार्मेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री विजय पुरम

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में विभाग द्वारा जारी की गई अन्य सभी शर्तें, नियम एवं हॉल टिकट यथावत रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी दूरभाष संख्या 03192–233233/241874 पर संपर्क कर सकते हैं।

तीस एएनएम एवं पच्चीस सीएचओ को एनीमिया मुक्त भारत पर प्रशिक्षित किया गया

श्री विजय पुरम, 31 दिसंबर

एएनएम एवं सीएचओ के लिए एनीमिया मुक्त भारत विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 29 दिसंबर, 2025 एवं 30 दिसंबर, 2025 को यहां के जंगलीघाट स्थित आयुष अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों, किशोरों, महिलाओं एवं गर्भवती माताओं में एनीमिया से मुकाबला करना था तथा पोषण में सुधार, आयरन युक्त आहार को बढ़ावा देने और आयरन एवं फोलिक एसिड की पूरकता प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया गया। कार्यक्रम में डॉ. एच. एम. सिद्धाराजू, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, डॉ. बी. अजित कुमार, लिंक अधिकारी एवं उप निदेशक (एफडब्ल्यू) तथा डॉ. कल्याण पी. कड़भाने, उप निदेशक (आयुष) की गरिमामयी उपस्थिति रही।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं सामुदायिक स्तर पर टी3 (टेस्ट, ट्रीट और टॉक) शिविरों के माध्यम से जागरूकता सृजित करने पर बल दिया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उक्त प्रशिक्षण के लिए डॉ. भवानी प्रसाद एस. एम., सहायक प्राध्यापक (मेडिसिन), अनिम्स, डॉ. मितुल साहा, सीनियर रेजिडेंट, सामुदायिक चिकित्सा, अनिम्स तथा डॉ. रोहित, एसएनओ, यूएनडीपी संसाधन व्यक्ति रहे। कुल मिलाकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से 30 एएनएम एवं 25 सीएचओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आवारा कुत्तों के काटने से बचाव पर स्कूलों में चला जागरूकता अभियान

श्री विजय पुरम, 1 जनवरी

आवारा कुत्तों के काटने से बचाव और प्रबंधन विषय पर द्वीपव्यापी जन–जागरूकता अभियान के तहत, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने 26 दिसंबर, 2025 को दो विशेष सत्र आयोजित किए। ये सत्र प्रोथरापुर के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, पत्थरगड्डा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आयोजित किए गए।

प्रोथरापुर स्कूल में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वी. सुब्रमण्यम ने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। सत्र में आवारा और पालतू कुत्तों के आसपास सुरक्षित व्यवहार, काटने की स्थिति में तत्काल प्राथमिक उपचार, घाव को अच्छी तरह धोने का महत्व, समय पर सूचना देने की आवश्यकता तथा आवारा कुत्तों की मानवीय संख्या नियंत्रण में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की वैज्ञानिक भूमिका पर जानकारी दी गई।

इसी प्रकार, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, पत्थरगड्डा में छात्रों और शिक्षकों को कुत्तों में आक्रामकता के संकेत पहचानने, काटने की संभावना बढ़ाने वाली परिस्थितियों से बचने, सड़क किनारे आवारा कुत्तों को भोजन न देने जैसी ज़िम्मेदार सामुदायिक आदतों और नसबंदी व टीकाकरण अभियानों का समर्थन करने के बारे में जागरूक किया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सत्रों में रोचक संवाद हुए, जहाँ छात्रों ने व्यावहारिक प्रश्न पूछे, जिनका धैर्यपूर्वक समाधान किया गया।

पैन–आधार नियमों से लेकर 8वें वेतन आयोग तक, 1 जनवरी से हो रहे ये वित्तीय बदलाव

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ देश में कुछ ऐसे नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। आज गुरुवार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। केंद्र सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकार ने 1 जनवरी 2026 से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लागू की गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसके साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने नए साल से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया है। सीएनजी की कीमतें जहां 3 रुपए सस्ती हो गई हैं, जबकि पीएनजी की कीमतें 0.70 रुपए सस्ती हो गई हैं। हालांकि देश के अलग–अलग शहरों में अलग–अलग कीमतें लागू होंगी। एक जनवरी से क्रेडिट स्कोर में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फिलहाल क्रेडिट स्कोर महीने में एक बाद अपडेट होता है, लेकिन 2026 से यह हर हते यानी हर 7 दिनों में अपडेट होगा। इससे ईएमआई समय से भरने का फायदा जल्द ही मिलेगा। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 थी। अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड एक जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स भरने से लेकर बैंकों में बड़े लेनदेन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का फायदा लेने वालों के लिए नया सिस्टम किसान आईडी पेश किया है। एक जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में यह सिस्टम लागू हो रहा है। इस डिजिटल आईडी में किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक आदि की जानकारी होगी। अगर यह आईडी नहीं है तो पीएम किसान योजना के तहत आने वाली 6,000 रुपए की सालाना मदद रुक सकती है। (इनपुट–आईएएनएस)

BSNL की सभी सर्कलों में राष्ट्रव्यापी वॉयस ओवर वाई–फाई सेवाएं शुरू

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

दूरसंचार प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड (**Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)**) ने वॉयस ओवर वाई–फाई (वीओ वाई–फाई) सेवा जिसे वाई–फाई कॉलिंग भी कहा जाता है, के राष्ट्रव्यापी विस्तार की प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की। यह उन्नत सेवा अब देश के प्रत्येक दूरसंचार सर्कल में सभी बीएसएनएल ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।

संचार मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि यह सेवा अब देश के सभी दूरसंचार सर्किलों में बीएसएनएल ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। वीओ वाई–फाई ग्राहकों को वाई–फाई नेटवर्क पर वॉयस कॉल और संदेश भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे घरों, कार्यालयों, बेसमेंट और दूरदराज के स्थानों जैसे कमजोर मोबाइल सिग्नल वाले क्षेत्रों में स्पष्ट और विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। वीओ वाई–फाई आईएमएस–आधारित एक सेवा है जो वाई–फाई और मोबाइल नेटवर्क के बीच निर्बाध हैंडओवर का समर्थन करती है। कॉल ग्राहक के वर्तमान मोबाइल नंबर और फोन डायलर का उपयोग करके किए जाते हैं जिसके लिए तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है।

बृंदाबन पंचायत में नशीले पदार्थों के

पृष्ठ 1 का शेष

एंटी–नारकोटिक्स (सीआईडी) के सहायक उप निरीक्षक श्री सूर्य नारायण ने एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों सहित कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। समाज कल्याण निदेशालय की परियोजना समन्वयक सुश्री एंचम्मा ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नशा समस्या की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का समापन श्री रोहित परोई, परियोजना समन्वयक–सह–व्यावसायिक परामर्शदाता, डीडीआर/आईआरसीए द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

शपथ पत्र

मैं, चंदन मिश्रा, पुत्र देवनारायण मिश्रा, निवासी एच.क्यू, एएनसी हैडो, श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि :

1. मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और उपर्युक्त पते पर निवास करता हूँ।
2. कि मेरे पिता का नाम मेरे आधार कार्ड संख्या 5781 9809 1824 में देवनारायण मिश्रा के रूप में दर्ज है।
3. कि मेरे पिता का नाम मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में देवनारायण मिश्रा के रूप में दर्ज है।
4. कि देवनारायण मिश्रा और देवनारायण मिश्रा एक ही एवं समान व्यक्ति है तथा वे मेरे पिता है।
5. कि मैं यह शपथ पत्र इस उद्देश्य से दे रहा हूँ कि उपर्युक्त वर्णित भिन्न नाम एक ही एवं समान व्यक्ति के हैं और भविष्य में मेरा नाम चंदन मिश्रा, पुत्र देवनारायण मिश्रा के रूप में माना जाए, ताकि नया पासपोर्ट प्राप्त किया जा सके।

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान : श्री विजय पुरम — शपथकर्ता

प्रेस नोट

नियमित मजदूर, समूह 'C' पद हेतु चयनित, सुश्री एफ. डेजी (रोल नं. 1100005524), पुत्री श्री वी. फ्रांसिस, निवासी गाराचरामा, श्री विजय पुरम, को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से पाँच (05) दिवस के भीतर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कृषि निदेशालय से संपर्क करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। निर्धारित अवधि में संपर्क न करने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता निरस्त मानी जाएगी।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
कृषि निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन

यूएई में 'डेजर्ट साइक्लोन–II' अभ्यास का समापन

नई दिल्ली, 01 जनवरी। अबू धाबी (यूएई) के अल–हमरा ट्रेनिंग सिटी में भारत–यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन–II' का सफल समापन हुआ। यह अभ्यास भारतीय सेना और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण का दूसरा संस्करण था।

जन संपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि 18 से 30 दिसंबर तक आयोजित यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच गहरी रक्षा साझेदारी का प्रतीक है और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभ्यास के दौरान शहरी वातावरण में अंतर–संचालनीयता, आपसी विश्वास तथा परिचालन तालमेल को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए कक्षा आधारित प्रशिक्षण और क्षेत्र आधारित अभ्यासों का संतुलित संयोजन किया गया।

सुरक्षित, सशक्त और विकसित भारत की ओर गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक सफर

नई दिल्ली, 01 जनवरी। साल 2025 गृह मंत्रालय के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। इस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षित, संरक्षित और विकसित भारत के विज़न को पूरा करने की दिशा में कई बड़े और निर्णायक कदम उठाए गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया।

मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों में वामपंथी उग्रवाद का लगभग अंत, प्रभावी आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ, नए आपराधिक कानूनों का सफल क्रियान्वयन, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और जनगणना 2027 की तैयारियाँ शामिल रहीं।

इन पहलों के कारण हिंसा में कमी आई, सजा की दर बढ़ी और वंचित वर्गों को सशक्त किया गया।

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत–
मोदी सरकार के नेतृत्व में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अभियान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया।

सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर केवल 3 रह गई, प्रभावित जिलों की संख्या 11 रह गई और 2025 में 312 नक्सली मारे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है।
करेंगुट्टा हिल्स ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर किए गए।
नारायणपुर में 27 खतरनाक माओवादी मारे गए, जिनमें टॉप नेता बसवराजू भी शामिल था।
258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली भी थे।
बोकारो क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल–मुक्त घोषित किया गया।

आतंकवाद पर सख्त प्रहार–
ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जरिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क को करारा झटका दिया गया।
आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और पीलगंज हमले में शामिल सभी आतंकियों को ढेर किया गया।
नई Multi-Agency Centre, BHARATPOL पोर्टल, NATGRID, CCTNS और कड़े कानूनों के जरिए आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को कमजोर किया गया।
NIA की सजा दिलाने की दर 95 प्रतिशत पहुंच गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची दरों में शामिल है।

जम्मू–कश्मीर में शांति और एकीकरण–
अब तक 12 हुर्रियत–समर्थित संगठन अलगाववाद छोड़कर संविधान पर भरोसा जता चुके हैं।
सीमा हमलों से प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी दी गई।
'वतन को जानो' जैसे कार्यक्रमों से कश्मीरी युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक व्यवस्था मजबूत–
e-Zero FIR प्रणाली शुरू की गई, जिससे 10 लाख रुपए से ऊपर की साइबर ठगी में FIR अपने–आप दर्ज होती है।
देशभर में फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और CFSL लैब्स स्थापित किए गए।
साइबर अपराध से निपटने के लिए चार–स्तरीय रणनीति लागू की गई।

नए आपराधिक कानून–न्याय का नया युग
तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जिनसे FIR से लेकर फैसला आने तक समयसीमा तय की गई।
न्याय प्रणाली को पारदर्शी, तेज़ और पीड़ित–केंद्रित बनाया गया।

ड्रग्स के खिलाफ युद्ध–
देशभर में करोड़ों रुपये के ड्रग्स जब्त किए गए।
1.37 लाख किलो ड्रग्स नष्ट किए गए (4,800 करोड़ मूल्य)
दिल्ली में 328 किलो मेथामफेटामिन, समुद्री सीमा पर 300 किलो ड्रग्स पकड़े गए।
ड्रग माफियाओं के खिलाफ 'Zero Tolerance' नीति लागू।

सीमा प्रबंधन और विदेश नागरिक नीति–
नई इमिग्रेशन नीति लागू की गई– जो टेक्नोलॉजी आधारित और राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रित है।
नया OCI पोर्टल लॉन्च किया गया।
Vibrant Villages Programme के तहत सीमावर्ती गांवों को विकसित किया गया।

आपदा प्रबंधनः Zero Casualty नीति–
भारत वैश्विक आपदा प्रबंधन लीडर के रूप में उभरा।
SDRF में 15,554 करोड़ रुपए और NDRF में 2,267 करोड़ रुपए की मदद राज्यों को दी गई।
आपदा में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए रिकॉर्ड संख्या में NDRF टीमें तैनात की गई।

पूर्वोत्तर भारत में शांति और विकास–
हिंसा में 70 प्रतिशत की कमी और नागरिक हताहतों में 85 प्रतिशत की गिरावट आई।
बोडोलैंड, मिजोरम और मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास तेज हुए।

CAPFs का आधुनिकीकरण–
CRPF ने 400 से अधिक नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए।
BSF ने 118 पाकिस्तानी चौकियां तबाह कीं।
सेवानिवृत्त जवानों को एक रैंक ऊंचा सम्मान देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया।

जनगणना 2027 और जाति जनगणना
2027 की जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल की जाएगी।

भारतीय भाषाओं को बढ़ावा
भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई।
राजभाषा विभाग को नया विस्तार मिला।

साल 2025 में गृह मंत्रालय ने देश को नक्सल–मुक्त, आतंक–मुक्त, साइबर–सुरक्षित और न्याय–केंद्रित भारत की दिशा में निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया

नई दिल्ली, 01 जनवरी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने गुरुवार को अपने नए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। नया लोगो राष्ट्र के विकास में आंकड़ों के महत्व को दर्शाता है और भारत के डेटा–आधारित शासन, पारदर्शिता तथा प्रगति को सुगम बनाने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान से प्रेरित यह लोगो मंत्रालय के "विकास के लिए डेटा" के संदेश को दर्शाता है। लोगो में अशोक चक्र, सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। मध्य में स्थित रुपये का चिह्न आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है।

वहीं, ऊपर की ओर बढ़ती विकास रेखा प्रगति को दर्शाती है और बताती है कि विश्वसनीय डेटा सतत आर्थिक विकास की कैसे सहायता करता है। केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता, स्थायित्व और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आधिकारिक आंकड़ों के भरोसे और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर, "सांख्यिकी" प्रस्तुत किया है। यह एक मैत्रीपूर्ण और लोक–केंद्रित चरित्र है, जिसे देश भर के लोगों के लिए आंकड़ों को सरल, समझने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए बनाया गया है। यह शुभंकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मूल मूल्यों, सटीकता, पारदर्शिता और डेटा–आधारित शासन को दर्शाता है और आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत करता है जो आम जनता के लिए समझना सरल है।

एक भरोसेमंद और बुद्धिमान आकृति के रूप में डिज़ाइन किया गया, "सांख्यिकी" जटिल सांख्यिकीय अवधारणाओं को सरल और दृश्य तरीके से समझाने में मदद करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सार्वजनिक पहचान के रूप में, इस शुभंकर का उपयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों, जागरूकता अभियानों, शैक्षिक सामग्री, डिजिटल प्लेटफार्मों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में किया जाएगा।

5जी, 6जी मिशन और 100 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन के साथ संचार मंत्रालय के लिए 2025 रहा ऐतिहासिक

नई दिल्ली, 01 जनवरी। केंद्रीय संचार मंत्रालय के लिए यह साल अभूतपूर्व रहा। इस साल मंत्रालय ने छात्र, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं और बुजुर्गों सहित सभी को तेज नेटवर्क, सस्ते डेटा और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं मुहैया कराईं। मंत्रालय ने 5जी सेवाएं देश के अंतिम कोने तक पहुंचाकर, स्वदेशी चौथी पीढ़ी स्टैक का सफल रोलआउट कर दिया। इससे भारत स्वदेशी चौथी पीढ़ी स्टैक का सफल रोलआउट करने वाला विश्व का पांचवां देश बन गया। इसके अलावा मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की शुरुआत कर इंटरनेट का कनेक्शन 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार देश में सभी राज्यों में 5जी इंटरनेट को पहुंचाया गया। इसकी मदद से युवाओं ने घर बैठे फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल स्टार्टअप शुरू किए। छोटे दुकानदारों, ठेला और रेहड़ी–पटरी वालों ने क्यूआर कोड, यूपीआई और ऑनलाइन भुगतान को अपनाया, जिससे उनका कारोबार बढ़ा और नकद पर निर्भरता कम हुई। 5जी सेवाएं सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध हो गईं। 99.9 प्रतिशत जिलों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई और लगभग 85 प्रतिशत आबादी 5जी कवरेज के दायरे में आ गई। देश में अक्टूबर 2025 तक देशभर में 5.08 लाख पांचवीं पीढ़ी बेस ट्रांससीवर स्टेशन स्थापित किए गए। इससे नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार हुआ, कॉल ड्रॉप में कमी आई और डेटा स्पीड में बड़ा उछाल देखने को मिला।

दूरसंचार विभाग ने सुनिश्चित किया कि डिजिटल सुविधाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें। ग्रामीण भारत को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत फाइबर नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार किया। वर्ष 2019 में जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई 19.35 लाख रूट किलोमीटर थी, वह बढ़कर 42.36 लाख रूट किलोमीटर हो गई। जिससे 2,14,843 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ गईं। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि 42.9 प्रतिशत रही, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी है।

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पहुंच के मामले में भी वर्ष 2025 ऐतिहासिक रहा। जून 2025 में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या 100.29 करोड़ रही, जो देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। सितंबर 2025 तक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन 99.56 करोड़ तक पहुंच गए थे। प्रति वायरलेस औसत मासिक डेटा खपत 2014 की तुलना में 399 गुना बढ़कर 24.01 जीबी हो गया। मोबाइल ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड अक्टूबर 2025 में 131.47 मेगाबिट प्रति सेकंड तक पहुंची, जो दुनिया के सबसे तेज नेटवर्क वाले देशों में भारत को शामिल करती है। आम नागरिकों को सस्ती सेवाओं का लाभ देते हुए एक जीबी डेटा की औसत लागत मात्र 0.10 अमेरिकी डॉलर रही, जो वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती दरों में से एक है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने ध्यान खींचा, साल के आखिरी दिन 60 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे

नई दिल्ली, 01 जनवरी। साल 2025 के आखिरी दिन और नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ी। गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आसपास के आकर्षण नए साल के जश्न के लिए सबसे पसंदीदा स्पॉट बनें। 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन यहां 60,000 से अधिक पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बसों, पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ा दिया।

नए साल को देखते हुए स्लॉट में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा किया गया। पहले जहां 500 पर्यटकों की एंट्री होती थी, लेकिन अब रोजाना 5,500 तक पहुंच गई है। अब कुल 7,000 पर्यटकों को एंट्री मिल रही है। पर्यटकों का कहना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी, गार्डन और अन्य आकर्षणों के साथ यहां स्वच्छता और व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाता है।

कई पर्यटकों ने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार वल्लभभाई पटेल की मेहनत और समर्पण का सम्मान करने का बेहतरीन तरीका बताया है। वडोदरा से आई पर्यटक हार्वी ने कहा कि मुझे यहां बहुत अच्छा लगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा जंगल सफारी जैसी कई दिलचस्प चीजें हैं।

युक्ता ने बताया कि हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी। यहां स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है। परिवार के साथ सभी को यहां जरूर आना चाहिए। एक अन्य पर्यटक ने कहा कि इस जगह की तारीफ का एक ही कारण है, हमारे देश के लिए की गई कड़ी मेहनत का सम्मान। हम यहां साल का आखिरी दिन मनाने और यहां के सुंदर कार्य, समर्पण को देखने आए हैं।

क्रिसमस के बाद से ही यहां पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अथॉरिटी और टेंट सिटी होटलों ने नए साल के जश्न के लिए गाला डिनर, क्रूज, डांस पार्टी और अन्य आयोजन तैयार किए थे। अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कुल 2.85 करोड़ से अधिक पर्यटक रजिस्टर हो चुके हैं।

एनपीएस मैनेज करने के लिए खुद पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे बैंक, पीएफआरडीए ने लिया अहम फैसला

नई दिल्ली, 01 जनवरी। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने देश में पेंशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम के टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी है। गुरुवार को घोषित इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते औपचारिकता के बीच अधिक लोगों को जोड़ना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

सुधारों की एक खास बात यह है कि अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक खुद पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे और NPS का प्रबंधन कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "PFRDA के बोर्ड ने पेंशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को NPS का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एक ढांचे को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। प्रस्तावित ढांचा मौजूदा नियामक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है जिन्होंने अब तक बैंकों की भागीदारी को सीमित कर दिया था।"

पहले, कुछ नियमों की वजह से बैंक पेंशन फंड प्रायोजक के तौर पर ज्यादा हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। अब नए मंजूर ढांचे में, बैंकों को नेट वर्थ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार वित्तीय मजबूती जैसे स्पष्ट पात्रता मानदंड तय करके इन बाधाओं को दूर किया जाएगा। PFRDA के अनुसार, इन विस्तृत मानदंडों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा और यह नए और मौजूदा दोनों पेंशन फंडों पर समान रूप से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पेंशन बाजार गहरा होगा और NPS ग्राहकों के लिए सुरक्षा मजबूत होगी।

इतिहास के पन्नों में 02 जनवरी : आज ही के दिन हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत

नई दिल्ली, 01 जनवरी। 02 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज है। इसी दिन वर्ष 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की औपचारिक शुरुआत की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने इन सम्मानों की स्थापना कर राष्ट्र सेवा के लिए असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करने की परंपरा को मजबूत आधार दिया।

भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन और बाद में खेल जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाली विभूतियों को प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में यह सम्मान केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन एक वर्ष बाद इसमें मरणोपरांत सम्मान देने का प्रावधान जोड़ा गया।

समय के साथ भारत रत्न के दायरे का विस्तार हुआ और खेल जगत में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता देता है, बल्कि देश के प्रति समर्पण और सेवा भावना का भी प्रतीक माना जाता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1757 – राबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता (कोलकाता) को वापस छीना।
1899 – रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कलकत्ता (कोलकाता) स्थित बेलूर मठ में रहने लगे।
1941 – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले से ब्रिटेन के कार्डिफ शहर स्थित लेनडॉफ कैथेड्रल को भारी नुकसान।
1942 – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर क़ब्ज़ा किया।
1954 – पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी, 1954 में की गयी।
1973 – जनरल एस. एफ. ए. जे. मानिक शॉ को फ़ील्ड मार्शल बनाया गया।
1989 – रणसिंघे प्रेमदास श्रीलंका के राष्ट्रपति बने।
1991 – तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया।
2001 – बांग्लादेश में 'फ़लवा' अवैध घोषित।
2008 – बलिया लोकसभा सीट पर हुए उप–चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर विजयी रहे।
2008 – सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली समन हसनैन वर्ष, 2002 की मिसेज पाकिस्तान वर्ल्ड चुनी गईं।
2008 – चिली का दक्षिणी लाइमा ज्वालामुखी फटा।
2009 – रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बाज़ार में 20 करोड़ रुपये के राहत पैकेज देने का निर्णय लिया।
2009 – भारत के सौरभ घोषाल स्क्वैश रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने।
2010 – उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण पाँच ट्रेनों की दुर्घटना में 10 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 40 घायल हो गए।
2016 – सऊदी अरब के जाने माने शिया मौलवी निम्र अल निम्र और 46 अन्य साथियों को सरकार की ओर से फाँसी दी गई।
2020 – भारत सरकार ने चंद्रयान–3 अभियान को मंजूरी दी।

केंद्र सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को किया अधिसूचित, लोगों से सुझाव मांगे

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों पर जारी चार नई श्रम संहिताओं के लिए बुधवार को मसौदा नियम जारी कर दिए। इन पर आम लोगों और हितधारकों से राय मांगी गई है। इन नियमों के लागू होने के बाद ही नए श्रम कानून पूरी तरह से प्रभावी हो पाएंगे।

चार श्रम कानून– वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों की संहिता 2020 की अधिसूचना 21 नवंबर को ही जारी हो चुकी है।

सरकार का लक्ष्य है कि एक अप्रैल 2026 से ये सभी संहिताएं पूरे देश में एक साथ पूरी तरह लागू हो जाएं। श्रम मामलों के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने से यह जरूरी है कि राज्यों के स्तर पर भी इनके लिए नियम बनाए जाएं। इसलिए राज्य सरकारें भी इन नियमों को आधिकारिक रूप से प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध संहिता पर 30 दिन और बाकी तीन श्रम संहिताओं पर 45 दिन का समय हितधारकों को सुझाव देने के लिए दिया है। इससे उद्योग और अन्य पक्ष स्पष्ट एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

मसौदा नियमों के लागू होने के बाद श्रमिकों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र, 40 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, समान कार्य के लिए समान वेतन और महिलाओं के लिए विभिन्न पालियों में समान अवसर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

सरकार का उद्देश्य इन चार संहिताओं के लागू होने के साथ श्रम संरक्षण का दायरा बढ़ाना, व्यापार संचालन को सुगम बनाना और श्रमिक–केंद्रित श्रम परिवेश को बढ़ावा देना है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "चार श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों का प्रकाशन श्रम सुधारों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम उद्योग को भरोसे के साथ तैयार होने, नियमों का पालन सरल बनाने और टिकाऊ वृद्धि के साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में मदद करेंगे।"

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने इस महीने कहा था कि नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि केंद्र और राज्यों ने पहले मसौदा नियम प्रकाशित किए थे लेकिन अब इन्हें वर्तमान समय एवं जरूरतों के हिसाब से अद्यतन करने की जरूरत है। श्री मांडविया ने कहा था कि सरकार मार्च, 2026 तक 100 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य हासिल करना चाहती है जो संख्या फिलहाल 94 करोड़ है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 वर्ष पूरे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य से जुड़ी है योजना

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

यह सही है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।

योजना के प्रमुख तथ्य (2026 की स्थिति के अनुसार):

उद्देश्यः इस योजना का मुख्य लक्ष्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को होने वाली मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना और उन्हें उचित आराम व पोषण के लिए प्रोत्साहित करना है।

नकद प्रोत्साहनः पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

संशोधित लाभः

पहले बच्चे के लिएः 5,000 रूपए की राशि दो किश्तों में दी जाती है।

दूसरे बच्चे के लिएः यदि दूसरा बच्चा बालिका (लड़की) है, तो सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 6,000 रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान करती है।

पात्रताः यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में नहीं हैं।

लाभार्थी इस योजना के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर पंजीकरण करा सकते हैं।

साथ ही, PMMVY के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

यह योजना न केवल मातृ मृत्यु दर को कम करने में सहायक है, बल्कि नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और टीकाकरण सुनिश्चित करने में भी बड़ी भूमिका निभा रही है।

70 लाख से अधिक आबादी वाला देश का पहला स्लम–फ्री शहर बनने की ओर अग्रसर सूरत

सूरत, 01 जनवरी।

गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत देश का पहला ऐसा महानगर बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसकी आबादी 70 लाख से अधिक होने के बावजूद वह स्लम–फ्री (झुग्गी–मुक्त) शहर बनेगा। यह जानकारी गांधीनगर में श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री जीतुभाई वाघाणी ने मीडिया को दी है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतु वाघाणी ने बताया कि श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान शहरी क्षेत्रों को स्लम–फ्री बनाने की जो दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी पहल की थी, उसके आज सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

वर्ष 2006 में सूरत की लगभग 38 प्रतिशत आबादी झुग्गी–बस्तियों में रहती थी। झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए पिछले दो दशकों में निरंतर योजनाबद्ध प्रयास किए गए। इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि आज सूरत में झुग्गी–बस्तियों में रहने वाली आबादी घटकर मात्र 5 प्रतिशत रह गई है। इससे सूरत में स्लम क्षेत्र लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं।

प्रवक्ता मंत्री वाघाणी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए सूरत को गुजरात का पहला स्लम–फ्री महानगर बनाने के लिए ठोस और परिणामोन्मुख कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं।

यदि सूरत यह उपलब्धि हासिल करता है तो वह देश का पहला इतना बड़ा स्लम–फ्री शहर बनेगा। हालांकि देश में पहले स्लम–फ्री शहर का दर्जा चंडीगढ़ को प्राप्त है, लेकिन वहां की आबादी करीब 10 लाख है। इसके मुकाबले सूरत की आबादी 70 से 80 लाख के बीच है, जिससे यह उपलब्धि आकार और जटिलता की दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ की भूमिका राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में संगठन की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैः रक्षा मंत्री

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही, उनकी प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की गहरी भावना की तारीफ की। डीआरडीओ आज गुरुवार को अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस संगठन की स्थापना 1958 में भारत को मजबूत बनाने और देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी, खासकर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई थी।

रक्षा मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "डीआरडीओ दिवस पर मैं सभी डीआरडीओ वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिल से बधाई देता हूं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है।"

श्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा, "स्वदेशी, भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी विकसित करके, डीआरडीओ हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है। मैं पूरे डीआरडीओ परिवार को सार्थक सफलताओं और राष्ट्र की निरंतर सेवा के एक साल की शुभकामनाएं देता हूं।"

डीआरडीओ का गठन साल 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रशासन के तहत, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का डिफेंस साइंस ऑर्गनाइजेशन के साथ विलय करके किया गया था। बाद में, साल 1979 में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस (डीआरडीएस) का गठन ग्रुप 'ए' अधिकारियों और वैज्ञानिकों की एक सेवा के रूप में किया गया, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती थी।

52 प्रयोगशालाओं के विशाल नेटवर्क के साथ, डीआरडीओ एयरोनॉटिक्स, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि युद्ध इंजीनियरिंग, जीवन विज्ञान, सामग्री, मिसाइल और नौसेना प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में लगा हुआ है।

आज, यह रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविध रिसर्च संगठन है। इस संगठन में डीआरडीएस के लगभग 5 हजार वैज्ञानिक हैं। साथ ही, लगभग 25 हजार अन्य अधीनस्थ वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी भी हैं, जो मिलकर देश की रक्षा क्षमताओं और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में योगदान देते हैं।

पहली बार कर्तव्य पथ पर देख सकेंगे डबल हंप ऊंट, जानें और भी क्या होगा खास

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ में पहली बार इंडियन आर्मी के डबल हंप ऊंट और जांस्कार पोनी के साथ ही ड्रोन को मार गिराने के लिए ट्रेंड किए गए इंगल (चील) भी दिखेंगे। आर्मी की रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के दस्ते में ये सब दिखाई देंगे। वेटरनरी कोर के इस दस्ते को कैप्टन हर्षिता लीड करेंगी।

आर्मी के वेटरनरी कोर में करीब तीन साल पहले ही महिला ऑफिसर्स को लेना शुरू किया गया और कैप्टन हर्षिता पहले बैच में शामिल थीं। ईस्टर्न लद्दाख की विषय परिस्थियों में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए डबल हंप ऊंट और जांस्कार पोनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दस्ते दस्ते में दो बैक्ट्रियन (दो कूबड़ वाले) ऊंट शामिल होंगे। करीब दो साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में एक नई पहल के तहत इनका इस्तेमाल शुरू किया गया।

इनका इस्तेमाल अंतिम छोर तक जरूरी सामान पहुंचाने और पठारी इलाकों की रेतीली जमीन में गश्त के लिए किया जाता है। ये माइनस 20 डिग्री तापमान में आराम से काम कर सकते हैं। है और 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई में इनका इस्तेमाल किया जा रहा। ये 200 किलो तक का वजन उठा सकते हैं।

ईस्टर्न लद्दाख में आर्मी जांस्कार पोनी का भी इस्तेमाल

कर रही है। ये मजबूत और सहनशील देशी नस्ल के घोड़े है, जो बेहद कठिन मौसम में भी कम बीमार पड़ते है। ये माइनस 40 डिग्री तापमान में भी काम कर सकते हैं। ये 70 किलो तक का वजन ढो सकते हैं।

रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर के दस्ते में चार रेप्टर्स भी दिखेंगे। ये ड्रोन को मार गिराने वाले चील है। जिन्हें इस तरह ट्रेड किया गया है जो पलभर में लपकर ड्रोन को नीचे गिरा सकते है। युद्धाभ्यास में कई बार इन्हें भी शामिल किया गया है और इनकी ट्रेनिंग जारी है। दस्ते में पांच इंडियन ब्रीड में 10 कैनाइन सोल्जर (ट्रेड (ट्रेड डॉग्स) भी होगे। ये मुढोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कॉम्बाई, राजा पलियम ब्रीड के है।

पाकिस्तानी एयर बेस पर बमबारी करने वाले एयर मार्शल नागेश कपूर बने देश के 50वें वायु सेना उप प्रमुख

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयर बेस पर बमबारी करने वाले एयर मार्शल नागेश कपूर को वायु सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभी तक दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व करने वाले इस अधिकारी ने गुरुवार को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह पदभार संभाल लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

एयर मार्शल नागेश कपूर ने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान उस समय संभाली थी, जब भारतीय वायु सेना ने पिछले साल 6–10 मई के बीच हुए ऑपरेशन में पाकिस्तानी एयर बेस पर कई हमले किए थे, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था। एयर मार्शल कपूर को 06 दिसंबर 1986 को वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के छात्र रहे हैं। क्वालिफाइड लाइंग इंस्ट्रक्टर और फाइटर कॉम्बैट लीडर होने के नाते तीन दशकों से ज्यादा के करियर में उनके पास अलग–अलग फाइटर जेट्स उड़ाने का 3400 घंटे से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने कई फील्ड और निर्देशात्मक नियुक्तियों पर काम किया है। उन्होंने कई तरह के कॉम्बैट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, जिनमें मिग–21 और मिग–29 के सभी वेरिएंट हैं।

देश के 50वें वायु सेना उप प्रमुख बने एयर मार्शल को

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी भूमिका के लिए स्वतंत्रता दिवस 2025 पर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, गणतंत्र दिवस 2025 पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2022 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2008 में उनकी सेवा के लिए वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान से पहले वे ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ के तौर पर काम कर चुके हैं। इससे पहले वे एयर ऑफिसर–इन–चार्ज पर्सनेल और सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, सेंट्रल एयर कमांड के तौर पर काम कर चुके हैं। एयर ऑफिसर नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और एयर फोर्स एकेडमी, डुंडीगुल के पूर्व छात्र हैं। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के भी छात्र रहे हैं।

सेहतमंद बनने के लिए बढ़ाएं एक और कदम, डॉक्टरों ने बताए नए साल में फिट रहने के 5 मंत्र

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

कैलेंडर बदल रहा है और हम भी इसके साथ बदलाव के लिए संकल्प ले रहे हैं। किसी को वजन कम करना है तो किसी को दिनचर्या सही करनी है। दरअसल, सेहत कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यह तो निरंतर छोटी–छोटी कमियों, गलतियों में सुधार लाकर स्वयं को बेहतर बनाने की तैयारी है। याद रहे कि हमें नया नहीं बनना बल्कि वास्तव में हम जो हैं उसमें ही सुधार करना है– जागरूक, जीवंत और व्यवस्थित पहल करनी है।

संकल्प की बात सुनते ही ज्यादातर लोग इसे औपचारिक मान बैठते हैं। कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं सोच रहे हैं। दरअसल, उत्साहपूर्वक संकल्प ले लिया जाता है और कुछ दिनों बाद प्रयास कम हो जाता है। कई बार तो संकल्प पूरा नहीं होने पर आत्मविश्वास कम होने लगता है। सेहत कम समय के लिए तय किया गया लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह शरीर, मन, भावनाओं के बीच जीवनभर के लिए सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया है। संकल्प पर अडिग रहें तो सफलता कठिन नहीं है।

यदि आप यह बात अच्छी तरह समझ जाएं तो सक्रिय बने रहेंगे। स्वस्थ रहने से आपकी ऊर्जा, समय और धन की बचत होगी और आप दूसरों की मदद के लिए आगे आ पाएंगे। एक ऐसा समाज बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं जो सकारात्मक रहे व खुशहाली के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।

समग्र स्वास्थ्य का मतलब केवल वजन और पेट के उभार को कम करना ही नहीं है। यह सदैव स्वयं और अन्य लोगों के प्रति जागरूक रहने का नाम है। बुद्धि व मन को निरंतर बेहतर करना है। जिम में मांसपेशियों को सुडौल बनाना अच्छा है, पर यह और अच्छा होगा यदि आप अपने भीतर करुणा लाएं। सामूहिक दायित्व उठाना बेस्ट एक्सरसाइज

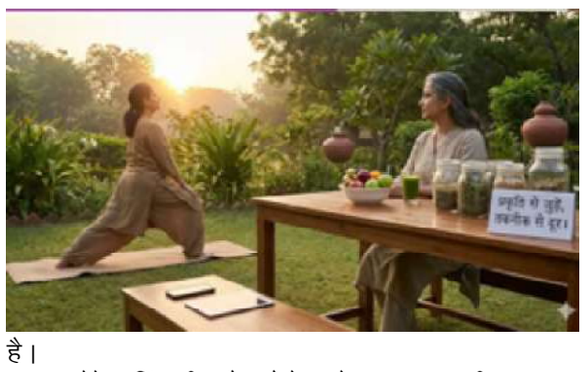

है।

कारपोरेट जिंदगी और गैजेट के कारण अच्छी गुणवत्ता पूर्ण नींद दुर्लभ हो गई है। नव वर्ष पर संकल्प लें कि अब नींद से समझौता नहीं करेंगे। शरीर को तरोताजा रखने व बीमारियों से दूर रहने के लिए हर रात समय पर सोएंगे। नींद कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर अगले दिन के लिए ऊर्जा भरती है। इससे तनाव से दूर रखने में मदद मिलती है।

हर दिन सजग होकर सांस की गति पर ध्यान देंगे, मौसमी फलों व सब्जियों का सेवन करेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। हर दिन होने वाली थकान आपका चुनाव है। इसके लिए प्रकृति की ओर चलें। सूर्य के प्रकाश, स्वच्छ हवा में यूं ही घूमने निकल जाएं। नंगे पांव जमीन पर चलें। प्रकृति को सम्मान देंगे तो वह भी हमें उतना ही प्रेम लौटाएगी। अपना सौ प्रतिशत दें

अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें। अधिकतम प्रयास पर भरोसा करें। केवल जीते चले जाने के बजाय और सुंदर तरीके से जीवन का प्रयोग कैसे करना है, इस दिशा में सोचें। इससे समग्र सेहत की ओर बढ़ सकेंगे।

नए साल में भारतीय हॉकी के सामने वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की बड़ी चुनौती

नई दिल्ली, 01 जनवरी।

साल 2025 में शानदार उपलब्धियों के बाद भारतीय हॉकी टीम 2026 में बेहद व्यस्त और अहम अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ कदम रख रही है। एक ओर जहां टीम की नजरें एफआईएच हॉकी विश्व कप में मजबूत प्रदर्शन पर होंगी। दूसरी ओर जापान में होने वाले एशियन गेम्स में खिताब बचाने की चुनौती भी सामने होगी।

नए साल की शुरुआत हीरो हॉकी इंडिया लीग (हीरो एचआईएल) के दूसरे सीजन से होगी, जो सफल वापसी के बाद एक बार फिर चर्चा में है। महिला हीरो एचआईएल का समापन 10 जनवरी को रांची में होगा, जबकि पुरुष हीरो एचआईएल 3 जनवरी से 26 जनवरी तक खेली जाएगी। इस दौरान मुकाबले चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में होंगे, जबकि फाइनल मैच कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा।

घरेलू सीजन के बाद भारतीय पुरुष टीम एफआईएच प्रो लीग के भारतीय चरण में हिस्सा लेगी। यह मुकाबले 10 से 15 फरवरी के बीच राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में होंगे। इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया में 21 से 25 फरवरी तक शेष प्रो लीग मैच खेलेगी। जून में प्रो लीग के अंतिम मुकाबले नीदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किए जाएंगे।

भारतीय महिला हॉकी टीम मार्च में एक अहम चुनौती का सामना करेगी। टीम 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद में

आयोजित विश्व कप क्वालिफायर में खेलेगी। यह टूर्नामेंट 2026 एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप (बेल्जियम और नीदरलैंड्स) में जगह बनाने का आखिरी मौका होगा। इस क्वालिफायर में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स और ऑस्ट्रिया जैसी मजबूत टीमें हिस्सा लेंगी।

साल का सबसे बड़ा आयोजन एफआईएच हॉकी विश्व कप अगस्त में खेला जाएगा। बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक होगा, जहां भारतीय टीम हालिया ओलंपिक सफलता को आगे बढ़ाते हुए पदक जीतने का लक्ष्य रखेगी।

सितंबर में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें 20वें एशियन गेम्स के लिए जापान के आइची–नागोया रवाना होंगी। यह महाकुंभ 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होगा। गत चैंपियन भारतीय पुरुष टीम खिताब बचाने के साथ–साथ लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधा क्वालिफिकेशन हासिल करने की कोशिश करेगी।